राजस्थान विधानसभा में चोर-डाकू की टिप्पणियों से काफी हंगामा मचा

बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने भाजपा को कांग्रेस के नेता चुराने वाला बताया तो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी कांग्रेस को ''डाकू'' कह दिया

-विधानसभा संवाददाता-

- दोनों विधायकों की इन टिप्पणियों से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई, हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर बाधित रही
- गोपाल शर्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ''मेरे पास कांग्रेस राज के 8 लाख करोड़ के घोटाले का ब्यौरा है, इसे मैं साथ लेकर आया हूं। एक पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया तो दूसरे पूर्व मंत्री को क्यों छोड़ दिया? वो छाती ठोक ठोककर कहते हैं हिम्मत है तो जेल भेजो।''

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस-भाजपा विधायकों ने एक-दूसरे की पार्टियों को चोर और डाकू बताकर टिप्पणियां की तो सदन में हंगामा मच गया।

शुक्रवार को बजट पर बहस के दौरान विधायक हरिमोहन शर्मा ने भाजपा को कांग्रेस के नेता चुराने वाला बताया तो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को डाकू बता दिया। दोनों विधायकों की इन टिप्पणियों से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर बाधित रही। हालांकि बाद में आसन में दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत करवाया।

दरअसल शुक्रवार को बजट पर बहस के दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि ''राजस्थान को गाडगिल फॉर्मूले में लाने वाले प्रणब मुखर्जी थे, जिनकी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आपने निंदा की थी।'' गोपाल शर्मा की चर्चा के दौरान बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने खडत्रे हो गए और उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि ''आप कांग्रेस-नेता चोर हो, मतलब कांग्रेस के नेताओं को ही चुरा लेते हो।''

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, ''यह रिकॉर्ड में जाना चाहिए, आप कह रहे हो कांग्रेस नेता चोर है।'' जिस पर गोपाल शर्मा ने कहा कि ''कांग्रेस नेता चोर नहीं, डाकू है।'' गोपाल शर्मा की इस टिप्पणी से सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणियां करते हुए नोंकझोंक शुरू कर दी। इसी बीच गोपाल शर्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ''मेरे पास कांग्रेस राज के 8 लाख करोड़ के घोटाले का ब्यौरा है, इसे मैं साथ लेकर आया हूं। एक पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया तो दूसरे पूर्व मंत्री को क्यों छोड़ दिया? वो छाती ठोक ठोककर कहते हैं हिम्मत है तो जेल भेजो।''

इस पूरे घटनाक्रम और बयानबाजी के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर तक बाधित रही। बाद में आसन ने दोनों पक्षों से समझाइश करते हुए मामला शांत कराया। देर शाम सदन की कार्यवाही 16 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

'गहलोत राज में डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते 19 बार पेपरलीक हुआ था'

जयपुर (विसं)। विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा।

जीनगर ने कहा कि भजनलाल सरकार का बजट प्रदेश को दिशा देने वाला है, डोटासरा इस पर सवाल उठा रहे थे। डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षकों के सम्मेलन में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने पूछा था कि क्या तबादलों में भ्रष्टाचार होता है तो शिक्षकों ने कहा था होता है, पैसा देना पड़ता है। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते अपने रिश्तेदारों को आरएएस में पास करवाया, चहेतों को नंबर दिलवाए। जिसके शिक्षा मंत्री रहते 19 बार पेपर लीक हुए वो आज नतीजों की बात कर रहे है। उस समय रिश्तेदारों को लिखित में कम अंक होने के बावजूद आरएएस के इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिलवाए।

जीनगर ने कहा कि गहलोत प्रदेश के भविष्य की चिंता की बात कर रहे थे। गहलोत 3 बार सीएम रह गए, तब तो जनता का भविष्य नहीं देखा। गहलोत ने सरकार में रहते अपने चहेतों, मंत्रियों की चिंता की। जनता की चिंता की होती तो विपक्ष में नहीं बैठते। लोग कोरोना में मर रहे थे, उस वक्त सरकार बचाने होटलों में बंद थे। लोग कोरोना में मर रहे थे और ये होटलों में मजे कर रहे थे।

'ब्लास्टिंग से चित्तौडगढ़ किले में दरारें पड़ रही'

जयपुर । विधानसभा में बजट बहस के दौरान शुक्रवार को भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उद्योगों की ब्लास्टिंग के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरारें पड़ रही है। राजस्थान अपनी संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली परंपराओं के कारण जाना जाता है। हर शहर की अपनी पहचान होती है, उस पहचान को कायम रखना होगा। विश्वराज सिंह ने कहा कि अरावली को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। अवैध खनन पर रोक लगानी होगी। नाथद्वारा में अनेक मगरे काटे जा रहे हैं, अवैध खान की जांच होनी चाहिए। हमें पर्यावरण को लेकर सोच बदलनी होगी। पर्यावरण हमें संभालता है।

जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर नोकझोंक हुई

जयपुर (विसं)। विधानसभा में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर मंत्री कन्हैयालाल और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो गई। भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा के सवाल के जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों पर कार्रवाई का जिक्र किया।

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक सवाल करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर केवल छोटे लेवल पर ही कार्रवाई की है। आपने दावा किया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आपने केवल जेईएन-एईएन ही सस्पेंड किए है या किसी आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की है? कौन सीनियर अधिकारी थे, जिनके साइन से टैंडर हुए। उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं?

मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में जो भी दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व जलदाय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी जो अधिकारी हैं, तत्कालीन एसीएस हैं, उनके खिलाफ भी हमने एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाया है। जो कोई दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अफसर का नाम बताइए। केवल गोलमाल किया जा रहा है, नाम बताइए। इसी बीच स्पीकर ने कहा कि नाम थोड़े ही बताया जाता है।

सदन में सवालों के जवाब देने में चूके उपमुख्यमंत्री बैरवा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा एक सवाल का जवाब देने के दौरान गलती कर गए। बैरवा भाजपा विधायक कल्पना देवी के लाडपुरा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन से जुड़े सवाल का जवाब देने खड़े हुए। इस दौरान बैरवा मूल सवाल की जगह संभावित सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब पढ़ने लगे। इस पर भाजपा विधायक कल्पना देवी ने टोकते हुए कहा कि यह तो मैंने अभी पूछा ही नहीं। जिस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उपमुख्यमंत्री बैरवा को टोकते हुए कहा कि आप गलत जवाब पढ़ रहे है, जवाब यह नहीं है। डिप्टी सीएम ने तत्काल गलती मानते हुए माफी मांगी।

ग्रामीण अस्पतालों में नहीं है डॉक्टर-कम्पाउन्डर : मेहर

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट बहस के दौरान कहा कि ''प्रदेश के ग्रामीण इलाके बेहाल हैं। अस्पतालों में डॉक्टर कंपांउडर नहीं हैं। जनता सोच रही है, डबल इंजन जा कहां रहा है, ले जा कहां रहा है? डबल इंजन की सरकार राजस्थान को गंगाजी ले जा रहा है।''

उन्होंने कहा कि बजट में न कोई कॉलेज और अस्पताल खोले हैं, न पानी- बिजली, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों पर ठोस काम किया है। एक विधायक को छह हैंडपंप और 3 ट्यूबबेल दिए हैं, ये वो कहां लगाएगा? विधानसभा क्षेत्र का इलाका बहुत बड़ा होता है, इतने से कैसे काम चलेगा? हमारी सरकार में हर विधायक को 100 हैंडपंप दिए जाते थे। इस सरकार में तो 6 हैंडपंप भी हमारे कहने से नहीं लगाए जाते। मेहर ने कहा कि बेवजह की घोषणाओं का मायाजाल गुमराह करने वाला है। पिछली बार टोडाभीम में बस स्टैंड की घोषणा की, वो आज तक नहीं बना। आपकी जेब में 100 रुपए है तो उतनी ही बात करो। लोगों को गुमराह करने के लिए 1000 रुपए की घोषणा मत करो।

मेहर ने कहा कि करौली के पहाड़ों पर 40 गांव बसे हैं, वहां आयरन की लीज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोहा अयस्क निकालकर गुजरात ले जाएंगे। किसानों को जमीन से हटा रहे हैं और उद्योगपतियों के लिए ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हैं। राजस्थान में कोई स्टील कारखाना नहीं है। किसानों को उजाड़कर लोह अयस्क गुजरात जाएगा।

सार-समाचार

66वीं कला प्रदर्शनी का उद्घाटन

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला-साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग प्रवीण गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित अकादमी संकुल में 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी की प्रशासक एवं जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने ''मेरा गांव मेरी धरोहर'' पोर्टल शुरू किया है। गाँव का व्यक्ति अपने क्षेत्र की कला धरोहर को इस पर अपलोड कर सकता है। पूरी दुनिया पर्यटन, कला संस्कृति का अनुभव करना चाहती है। आज कला और कलाकारों के लिए बेहतरीन अवसर हैं। आज के पुरस्कार वितरण समारोह में जिन 9 कलाकारों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया है, उन्हें हार्दिक बधाई। राजस्थान ललित कला अकादमी की प्रशासक एवं जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने कहा कि युवाओं को कला से जोड़कर ही देश का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस तरह की प्रदर्शनी में कलाकारों को अधिक से अधिक सहभागिता करनी चाहिए। कला संस्कृति के क्षेत्र में राजस्थान जैसा कोई प्रदेश नहीं है। अकादमी संकुल में आयोजित 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह में रमेश कुमार सैनी, विकास कुमार मिरोठा, जयन्त शर्मा, श्वेता नैना, मोहनलाल चौधरी, उर्मिला शर्मा, धीरज बलिहारा, करूणा, शिवपाल कुमावत को 25-25 हजार रूपये नकद, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया । इस अवसर पर विद्या सागर उपाध्याय, नाथूलाल वर्मा, महावीर भारती सहित कला जगत की कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन गौरव शर्मा ने किया। राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव डॉ. रजनीश हर्ष ने बताया कि यह कला प्रदर्शनी 13 से 19 फरवरी तक दर्शकों के लिए नि:शुल्क खुली रहेगी।

राज्यपाल के हाथों नीरज जैन सम्मानित

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के मुख्य आतिथ्य में जगतपुरा स्थित स्काउट गाइड के राज्य प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में प्रदेश स्काउट गाइड संगठन के जनसंपर्क प्रभारी एवं विभागीय मासिक पत्रिका के सहायक संपादक नीरज जैन को मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में पंचायत राज मंत्री अध्यक्ष रहे, जबकि विधायक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य के मार्गदर्शन एवं राज्य सचिव डॉ. पी.सी. जैन के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। अंत में डॉ. अखिल शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। नीरज जैन ने सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे गर्व का क्षण बताया और अवार्ड समिति तथा राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य के प्रति आभार जताया।

उच्च शिक्षा पर सम्मेलन 16-17 को

जयपुर । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत विकास, नेतृत्व क्षमता संवर्धन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शैक्षिणक गुणवत्ता उन्नयन को केंद्र में रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल की जा रही है। विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, तथा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 16 व 17 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा ने बताया कि यह दो दिवसीय सम्मेलन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संवाद, सहयोग और नीति-उन्मुख विमर्श का एक सशक्त राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा।

विधानसभा उद्यानकर्मियों को बधाई दी

जयपुर । राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित उद्यान को बेस्ट एक्जीबिटर ऑफ दी शो शील्ड प्राप्त होने पर उद्यान कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। स्पीकर देवनानी ने कहा कि यह सम्मान उद्यान विभाग की समर्पित मेहनत, सौंदर्यबोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं, बल्कि हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम स्थान बन रहा है। विधानसभा उद्यान में वर्तमान में लगभग 70 किस्मों के पुष्पीय पौधे लहलहा रहे हैं, जो परिसर की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। विभिन्न रंगों और प्रजातियों के फूल न केवल दर्शनीय वातावरण का सृजन कर रहे हैं, बल्कि आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं। स्पीकर देवनानी ने उद्यान कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम और नवाचार के माध्यम से विधानसभा परिसर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का यह प्रयास सराहनीय है।

राज्य के प्रथम 'नेफैड बाजार' का उद्घाटन

'किसान से किचन तक' की संकल्पना पर आधारित है नेफैड बाजार : दक

जयपुर । सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नेफैड) द्वारा शुरु किये गए रिटेल आउटलेट 'नेफेड बाजार' का फीता काटकर उद्घाटन किया। 'किसान से किचन तक' की संकल्पना पर आधारित इस 'नेफेड बाजार' के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में रिटेल आउटलेट 'नेफेड बाजार' का उद्घाटन किया।

दक ने कहा कि राज्य के इस प्रथम 'नेफैड बाजार' का शुभारम्भ किसानों की समृद्धि एवं उपभोक्ताओं की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 1958 से किसानों की सहकारी संस्था के रूप में नेफेड किसानों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस प्रकार की पहलें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेफेड बाजार न केवल उपभोक्ताओं को शुद्ध, प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएगा बल्कि किसानों के लिए स्थायी और लाभकारी विपणन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी 'नेफैड बाजार' स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी, नेफैड के निदेशक रामप्रकाश चौधरी सहित सहकारिता विभाग एवं नेफेड के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

रैपिडो बाइक चालक ने युवती से की छेड़छाड़

जयपुर । एक युवती को अकेले में रैपिडो कैब बुक करना भारी पड़ गया। शातिर रैपिडो चालक युवती को गलत जगह ले जाने लगा। इस पर पर युवती ने विरोध किया तो रैपिडो चालक ने उसे धमकी दी। इसी दौरान रैपिडो पर बैठी युवती को थोड़ा आगे जाकर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई तो युवती ने मदद के लिए शोर मचा दिया। लोगों को इकट्ठा होते देख रैपिडो चालक युवती को उतार कर फरार हो गया। जिसके बाद युवती ने मामले की जानकारी भांकरोटा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय युवती का आरोप है कि गुरुवार को उसने घर जाने के लिए रैपिडो बुक की थी। रैपिडो चालक उसे बाइक पर बैठाकर गलत रास्ते में ले गया। विरोध करने पर आरोपी रैपिडो चालक ने उसे धमकी दी। सुनसान जगह ले जाने लगा। तभी युवती को एक कंपनी के कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। युवती चिल्लाई तो आरोपी उसे उतारकर भाग छूटा।

'बी.सी.आर. कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी एजी की कमेटी क्यों गठित नहीं?'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और महाधिवक्ता से पूछा है कि बीसीआर की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित क्यों नहीं की गई है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 17 जुलाई, 2023 को पूरा हो गया था। इससे पूर्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 15 मई को इस कार्यकाल को छह माह के लिए बढा दिया। याचिका में कहा गया कि इस दौरान बीसीआई ने एडवोकेट्स प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम में संशोधन कर वकीलों के प्रैक्टिस प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम पूरा होने तक 26 जून, 2023 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस कार्यकाल को डेढ साल के लिए फिर से बढ़ा दिया । याचिका में कहा गया कि यह बढा हुआ कार्यकाल भी दिसंबर, 2024 में पूरा हो चुका है। ऐसे में एडवोकेट एक्ट की धारा 8ए के तहत महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी चाहिए थी। इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से बीसीआर को लीगल नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कौंसिल की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पिता ने आठ माह की बेटी की कैंची से गला रेतकर हत्या की

आरोपी सादाब ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया

जयपुर (कासं)। मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद एक पिता ने अपनी आठ माह की मासूम बेटी की कैंची से गला काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपित पिता से पूछताछ में जुटी है।

थानाधिकारी उदयभान यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी सादाब (19) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी शादी जुलाई 2025 में मालपुरा गेट स्थित अंबेडकर कॉलोनी निवासी रूकसार बानो (19) से हुई थी। दंपती की आठ माह की बेटी सहनाज थी।

करीब छह दिन पहले सादाब पत्नी और बेटी को लेकर ससुराल अंबेडकर कॉलोनी आया था। 6 फरवरी सुबह करीब 10 बजे गांव वापस लौटने की बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। पत्नी द्वारा कुछ दिन और रुकने की बात कहने पर सादाब ने मारपीट की और उसका गला दबाने का प्रयास किया। इस दौरान साले सोहिल ने बीच-बचाव किया। जिससे आरोपी और भड़क गया। बताया गया कि सादाब ने सोहिल के सिर पर स्टील की केतली से वार किया। शोर-शराबा सुनकर पडौसी मौके पर पहुंचे और दोनों को छुडाया। इसी बीच आरोपी ने बेटी सहनाज को सोहिल की गोद से छीन लिया और कमरे में बंद हो गया।

कमरे के भीतर सादाब ने कैंची से बच्ची का गला काट दिया और शव को कंबल में छिपा दिया। इसके बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों और पडौसियों ने दरवाजा तोड़ा तो आरोपी अंदर फंदे से लटका मिला। जिसे तुरंत नीचे उतारा गया, कमरे में तलाश करने पर बच्ची कंबल में लहूलुहान हालत में मिली। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पत्नी रूकसार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी सादाब को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है।

ओपीजेएस यूनिवर्सिटी बंद, 10 निजी विश्वविद्यालयों की जांच शुरू : बैरवा

-विधानसभा संवाददाता-

- उपमुख्यमंत्री ने सदन में कहा ''फर्जी डिग्री कांड पर राज्य सरकार ने लिया सख्त एक्शन''
- मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी फर्जी डिग्री प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है : बैरवा
- उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियामक आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है।

जयपुर । उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में फर्जी डिग्री कांड पर राज्य सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। फर्जीवाडे की गंभीर आरोपों के कारण चूरू जिले की ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी को बंद करते हुए 10 निजी विश्वविद्यालयों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यह जानकारी शुक्रवार को भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के प्रश्न के जवाब में दी।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि फर्जीवाडे के गंभीर आरोपों के बाद 7 जनवरी को ओपीजेएस विश्वविद्यालय का परिसमापन कर दिया है। यहां के प्रशासन की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त बीकानेर को सौंपी गई है। मामले में कई दोषी कार्मिकों और दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी तरह मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी फर्जी डिग्री प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विश्वविद्यालयों की जांच अभी जारी है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 10 विश्वविद्यालयों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर जांच शुरू की गई है।

जांच के दायरे में शामिल प्रमुख संस्थानों में सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनूं, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर, श्रीधर विश्वविद्यालय झुंझुनूं, माधव विश्वविद्यालय सिरोही, रैफल्स विश्वविद्यालय अलवर, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और जगदीश झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनूं शामिल है।

शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में अनियमितताओं के आरोपों के बाद कुछ विश्वविद्यालयों की समग्र जांच एसओजी को सौंपी गई है। पुलिस जांच में बैक डेट में डिग्रियां और अंकतालिकाएं जारी करने की शिकायतें सामने आईं। इस संबंध में ओपीजेएस विश्वविद्यालय के संचालक जोगेंद्र सिंह समेत कई पूर्व अधिकारी और कथित दलाल गिरफ्तार किए जा चुके है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के भी कुछ अधिकारियों को जेल भेजा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियामक आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले तैयार किए गए 'राजस्थान प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल-2023' के प्रावधानों को और मजबूत बनाने के लिए नई समिति गठित की गई है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। नया प्रारूप जल्द विधि विभाग को भेजा जाएगा। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित गाइडलाइन में भी संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण नीति पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं : टीकाराम जूली

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति का मुद्दा गर्माया रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाते हुए जमकर घेरा। जब शिक्षा मंत्री ने तबादलों के प्रावधान पर भ्रम की स्थिति पैदा की, तो जूली ने उन्हें सीधे सवालों के कटघरे में खडा कर दिया।

सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधे तौर पर पूछा कि सरकार का आधा समय बीत चुका है और सवा 2 साल से अधिक का वक्त हो जाने के बावजूद तबादला नीति अब तक क्यों नहीं बनी? उन्होंने सरकार से पूछा, ''क्या आप कोई टाइम-लाइन देना चाहेंगे कि आखिर कब इनके ट्रांसफर होंगे?''। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के लाखों शिक्षकों को गुमराह कर रही है, जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नीति बनाने का वादा किया था। सदन में जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली सरकारों के आंकड़ों और भाजपा के समय हुए 2200 तबादलों का हवाला दिया, तो नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ''कांग्रेस ने किए या भाजपा ने किए, उन पुरानी बातों को छोड़ें''। जूली ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि वर्तमान सरकार अपनी घोषणा के अनुसार नीति कब तक बनाएगी।

रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का उत्साह बरकरार

-कार्यालय संवाददता-

- योजना के आठवें चरण में 230 भूखंडों के लिये 380 आवेदन प्राप्त हुए

जयपुर । राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने तथा प्रदेश में नए उद्योग लगाने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 प्रारंभ की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उनकी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना है। मार्च-2025 से शुरू हुई इस योजना के अब तक आठ चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत जिन निवेशकों ने 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024' के दौरान प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित किए हैं, उनको आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटित किये जा रहे हैं।

इस योजना के सभी चरणों में अब तक 1548 भूखण्डों के लिए 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीतियों के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। आठवें चरण में भी निवेशकों का उत्साह उल्लेखनीय रहा है, जिसमें 230 औद्योगिक भूखण्डों के लिए 380 आवेदन प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी किये जा रहे हैं, इससे रीको को लगभग 343 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति होगी। इन भूखण्डों से करीब 1500 करोड़ रूपये का निवेश एवं लगभग 20 हजार लोगों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को रोजगार संभावित है।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि योजना के पूर्व के सात चरणों में 1230 निवेशकों को भूखण्ड आवंटित/ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं, इससे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। इन सात चरणों में लगभग 1985 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 320 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। निवेशकों की मांग को ध्यान में रखते हुए योजना में औद्योगिक भूखण्डों के साथ-साथ लॉजिस्टिक भूखण्डों को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर उपलब्ध हों इसलिये विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित इत्यादि के लिये भूखण्ड आरक्षित किये जाते